

# No notice served, say members as church on 'encroached' land razed

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE South Delhi district administration on Monday razed a church built upon "encroached" land during a demolition drive in Chattarpur. However, the church members termed the action "illegal", claiming that notice was not served to vacate the premises.

The district administration, in a statement, said the church was built on gram sabha land, which was "encroached by some people by installment of religious structures".

"Over the time, the encroachment started increasing in the garb of expansion of the religious structure. Therefore, the BDO office tried to undertake the demolition of unauthorised structures," it said.

## Built on gram sabha land, says dist administration

The district administration, in a statement, said the church was built on gram sabha land, which was "encroached by some people by installment of religious structures"

It added that the matter was earlier transferred to the "religious committee" upon the NHRC's directive.

"Thereafter, a letter was received from the Home Police-II Department dated 03/03/2021 where they cited the HC order of 2015 in WPC no 5234/2011 wherein it was directed to demolish the entire construction above the ground floor as well as portions of the ground where idols are not installed/

placed without waiting for the decision of the Religious Committee," the statement said.

According to a notice dated July 7, the office of the Block Development Officer (South) directed the "encroachers" to remove the encroachment within three days.

Meanwhile, Pastor council member and lawyer John Thomas claimed the church never received any notice. "Neither did we receive any notice, nor were we given time to vacate. The officers came with 150 police personnel and three JCBs and demolished the structure against the high court's order. We were not even allowed to retrieve our sacred things. This was a completely illicit act and we will take legal action," he added. *With PTI inputs*

## असम पुलिस पर फेक एनकाउंटर के आरोप: 40 दिन में गोलीबारी की 20 घटनाएं, 13 संदिग्ध मारे गए; दिल्ली के वकील की ...

<https://www.bhaskar.com/national/news/assam-police-face-fake-encounters-charge-delhi-based-advocate-complaint-nhrc-128692534.html>

असम पुलिस पर फेक एनकाउंटर के आरोप लगे हैं। राज्य में 40 दिन में ऐसी 20 घटनाएं हुईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान पुलिस की गोली से कम से कम 13 संदिग्ध अपराधी मारे गए। जबकि दुष्कर्म और पशु तस्करी के 10 से ज्यादा आरोपी घायल हुए।

असम में दो महीने पहले भाजपा नेता हेमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल में फेक एनकाउंटर बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर ने इस मामले में शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई है और दखल देने की मांग की है।

ट्रेंड पुलिस अधिकारियों से पिस्तौल छीने जाने पर भी सवाल वकील जवादर का आरोप है कि असम पुलिस ने फेक एनकाउंटर में छोटे अपराधियों को मार गिराया है। पुलिस कहती है कि अपराधियों ने उनसे हथियार छीन लिए और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। इस पर जवादर का सवाल है कि यह कैसे संभव है? एक ट्रेंड पुलिस अधिकारी से कोई कथित अपराधी हथियार कैसे छीन सकता है, जबकि पिस्तौल कमर की बेल्ट से बंधी होती है।

रविवार को भी एनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया। राज्य में नगांव जिले में रविवार को गोलीबारी की दो घटनाएं हुईं। इसमें नगांव के नजदीक ढिंग में पुलिस ने डकैत जैनल आबेदीन को मार गिराया। इस बारे में नगांव के एसपी आनंद मिश्रा ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि आबेदीन अपनी गैंग के साथ नागांव इलाके में एक घर को लूटने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने गोलियां दागनी शुरू कर दीं।

जवाबी कार्रवाई में आबेदीन घायल हो गया। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रविवार को ही दूसरी घटना में एक संदिग्ध ड्रग डीलर घायल हो गया।

ढिंग विधायक का आरोप- अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा। ढिंग विधायक अमीनुल इस्लाम ने भी एनकाउंटर को लेकर राज्य पुलिस पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फर्जी एनकाउंटर में ज्यादातर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।

विधायक ने आबेदीन का पक्ष लिया। उनका कहना है कि वे उसे जानते थे वह डकैत नहीं, बल्कि शराबी था।

मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर पैटर्न का सपोर्ट किया

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कुछ दिनों पहले ही एनकाउंटर्स को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई आरोपी सर्विस बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है या भागता है और अगर वह बलात्कारी है तो कानून ऐसे लोगों के पैर में गोली मारने की इजाजत देता है, न कि छाती में। जब किसी ने मुझसे पूछा कि क्या राज्य में एनकाउंटर का पैटर्न बन गया है तो मैंने कहा कि अगर अपराधी पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो (एनकाउंटर) पैटर्न होना चाहिए।

## असम फेक एनकाउंटर केस:दिल्ली के वकील की मांग-मानवाधिकार आयोग दखल दे

<https://hindi.thequint.com/news/india/assam-police-fake-encounter-case-delhi-based-lawyer-approaches-nhrc>

असम पुलिस (Assam Police) पर फर्जी एनकाउंटर (Fake Encounter) के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के एक वकील जवाहर ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि असम पुलिस "फर्जी एनकाउंटर" कर रही है और छोटे-मोटे अपराध के मामलों में आरोपियों का एनकाउंटर कर रही है। वकील ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप की मांग की है।

शिकायत के मुताबिक, हिमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से "मुठभेड़ की होड़" शुरू हुई है।

एनडीटीवी के मुताबिक, 1 जून से अब तक पुलिस गोलीबारी की 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें आरोपियों को हिरासत में या छापेमारी के दौरान गोली मार दी गई है। जिसमें से कम से कम पांच मामलों में आरोपी की मौत हो चुकी है।

हाल में हुए 'फर्जी मुठभेड़'

रविवार, 11 जुलाई को, मध्य असम के नगांव में दो गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं, जब पुलिस ने पश्चिमी असम के कोकराझार में एक कथित डकैत को गोली मार दी और एक अलग घटना में एक संदिग्ध ड्रग डीलर को घायल कर दिया।

असम पुलिस ने उसी दिन एक और कथित डकैत जैनल आबेदीन पर गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नगांव से करीब 28 किलोमीटर दूर ढिंग में मुठभेड़ हुई थी। मीडिया से बात करते हुए, नगांव के एसपी आनंद मिश्रा ने कहा,

"हमारे पास इनपुट था कि आबेदीन अपने ग्रुप के साथ बहुत ही कम समय में नगांव इलाके में एक घर को लूटने जा रहा है। अतिरिक्त एसपी धुरबा बोरा के नेतृत्व में, पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर उसके घर की तलाशी अभियान शुरू की और उसे अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस दल ने उन पर गोलियां चलाई और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।"

इस बीच, ढिंग के एक विधायक ने गोलीबारी को "अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने" के तौर पर पेश किया है। अमीनुल इस्लाम ने कहा, "असम पुलिस अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के फर्जी एनकाउंटर कर रही है। मैं पीड़ित के बारे में जो जानता हूँ, वह डकैत नहीं बल्कि एक शराबी था।"

जवादर ने क्या कहा?

वकील जवादर की शिकायत के मुताबिक, असम पुलिस इन फायरिंग के लिए अजब तर्क देती है, अक्सर छोटे-मोटे ड्रग डीलर, मवेशी तस्कर, डकैत जैसे छोटे-मोटे अपराधियों को फर्जी एनकाउंटर में मार रही है। पुलिस कहती है कि आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे।

एनडीटीवी के मुताबिक जवादर ने कहा,

"वकील ने यह भी कहा कि ऐसा संभव नहीं लगता कि वे पुलिस से उसकी पिस्टल छीनकर चला रहे होंगे। क्योंकि उनके सामने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी होंगे और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार होंगे। स बात पर भी यकीन करना मुश्किल है कि सभी आरोपी पहले से ट्रेंड पुलिस अफसर से उसकी पिस्टल छीन सकते हैं, क्योंकि वो पिस्टल एक रस्सी के जरिये उनकी कमर से बंधी होती है।

NHRC को अपनी तत्काल शिकायत में, उन्होंने आगे कहा, "पुलिस की कार्रवाई एक कथित अपराधी को कानूनी अधिकारों से वंचित कर रही है।"

अभी हाल ही में हिमंत बिस्वा सरमा ने बयान दिया था कि पुलिसकर्मियों को अपराधियों के पैरों पर गोली मारने के लिए कानून के तहत अनुमति है। जवादर की शिकायत में कहा गया है कि पुलिस कर्मी "बदले की भावना से फर्जी मुठभेड़" कर रहे हैं।

## Explained: Why is Kitex group unhappy with the Kerala govt

<https://indianexpress.com/article/explained/kitex-group-kerala-7401464/>

Hours after returning from Telangana, where he announced plans to invest Rs 1,000 crores in an apparel park in Warangal, Sabu M Jacob, the chairman and managing director of garments major Kitex Group, said his conscience doesn't allow him to invest a single rupee in Kerala, his home state, ever again. The remark caps the showdown between the home-grown company and the Kerala government.

What's the origin of the tussle between Kitex and Kerala govt?

The origin of the tussle lies in a series of inspections within the span of a month by various government departments including labour and health at the Kitex manufacturing unit and company premises in Kizhakkambalam in the eastern suburbs of Kochi in Ernakulam district.

Jacob alleged that the inspections were a way of "harassing" entrepreneurs like him and "pushing him into a corner". He alleged the officials who came down to inspect the company behaved as if they were looking to nab thieves and robbers.

However, the state's Industries Minister P Rajeev clarified that the government had not initiated any suo motu inspections on the company. While the industries department itself was not involved in ordering any raids, he said the inspections by health and labour departments were following orders by the Kerala High Court and the National Human Rights Commission based on individual complaints. The complaints purportedly raised issues of treatment of workers by the company and the pollution of a nearby river through effluent discharge.

Newsletter | Click to get the day's best explainers in your inbox

What happened after the inspections?

Though final results of the government inspections are awaited, Jacob took the spat with the government to the next level by declaring that he was abandoning investments to the tune of Rs 3,500 crores that were announced at the ASCEND summit in January 2020. The investments had been aimed at setting up an apparel park and industrial parks in Kochi, Thiruvananthapuram and Palakkad along the proposed economic corridor by 2025, generating thousands of jobs. Without directly naming anyone in the state government, Jacob charged that the state lacked a conducive climate for business to grow. He claimed while he did not want to abandon the proposed investments in Kerala, he was being forced to do it as a result of political and bureaucratic harassment. He said while other states in the country were quietly upgrading their eco-system for big business, Kerala was still stuck 50 years behind.

Last week, Jacob, along with a few of Kitex officials, flew in a private jet sent by the Telangana government to Hyderabad where they met a delegation led by the state's

Industries Minister KT Rama Rao. After two days of discussions, the company announced plans to invest Rs 1,000 crore in an apparel park at the Kakatiya Mega Textile Park in Warangal.

How has the Kerala govt responded to the row with Kitex?

CM Pinarayi Vijayan defended the state's business environment, stating that the government was doing everything it can to make entrepreneurs and investors feel comfortable in the state. He charged that Jacob's remarks were "motivated" with the aim of tarnishing the image of Kerala as a business-friendly destination. He said the state was ranked first in the sustainable development index prepared by the Niti-Aayog. He also listed measures by his government in the last five years such as setting up district-level dispute redressal forums, centralised system for inspections and a board for fast-track clearances of projects.

On his part, Rajeev repeatedly said the company management should not have made comments disparaging the state. He also said the government was ready to initiate talks with Kitex and resolve any issues.

What's the significance of Kitex Group?

The Kitex Group, founded by late MC Jacob in the 60s, is the second-largest producer of children's apparel in the world. Apart from garments, the company also manufactures aluminium products, curry powders and school bags. It is the largest private-sector employer in Kerala's industrial scene, believed to provide employment for nearly 10,000 people. Its operations are centred in the village of Kizhakkambalam on the outskirts of Kochi.

Does the row have political shades?

The row comes just months after Twenty-20, a CSR wing of Kitex Group, participated in the state's Assembly elections by nominating candidates in eight constituencies in Ernakulam district. Though it lost in all of the seats, it dented the prospects of the LDF and UDF candidates, especially in Kunnathunad. The Twenty20 was floated with the aim of making the Kizhakkambalam panchayat the best in the country by 2020. In the 2015 local body polls, the outfit won all except one ward in the local body, making it the first time a corporate firm has control over a panchayat in India. In the 2020 polls, it retained power in Kizhakkambalam and captured power in three other neighbouring panchayats, relegating the established political parties like the CPM, Congress and the BJP. Jacob's move to enter politics first through local bodies and then the Assembly is seen as having rubbed the political parties the wrong way.

## Lawyer moves NHRC against 'trigger happy' Assam cops

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/lawyer-moves-nhrc-against-trigger-happy-assam-cops/articleshow/84335133.cms>

A Delhi-based lawyer from Assam has lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) against the Assam Police for a series of encounters that have taken place ever since the Himanta Biswa Sarma-led government took charge two months ago. He also urged the rights body to take cognisance and institute an inquiry into these incidents. Arif Jwadder - who hails from Guwahati - in his complaint to the rights body on Saturday said 'small-time' criminals were being shot at by police and the reason cited for such "fake encounters" was that they tried to "flee from police custody after snatching weapons". Pointing out that over 20 such encounters had taken place recently, Jwadder in his complaint said most of the persons at the receiving end were alleged drug dealers and cattle smugglers. He added that a few of them have died on the spot which is a "violation of human rights".

"Assam chief minister recently stated at a conference that police should shoot at alleged criminals in the legs which is permitted by law. After this statement by the chief minister, police are staging fake encounters with impunity," Jwadder said. In his complaint, Jwadder mentioned 10 cases of encounters that occurred between May 23 and July 10 where the alleged criminals were either killed or injured when they "attempted to flee from police custody" at times after trying to snatch firearms from policemen. They include Bubu Konwar who wanted for several crimes including murder and sacked Railway Protection Special Force sub-inspector Kanwaldeep Singh Sidhu who was wanted for abducting a businessman.



## Church demolished in south Delhi, members cry foul

PTI ■ NEW DELHI

The south Delhi district administration on Monday razed a church built upon "encroached" land during a demolition drive in Chattarpur.

However, the church members termed the action "illegal", claiming that a notice was not served to vacate the premises.

The district administration, in a statement, said the church was built on the gram sabha land, which was "encroached by some people by installment of religious structures".

"Over time the encroached area started increasing in the garb of the expansion of the religious structure. Therefore, BDO office tried to undertake the demolition of the unauthorised structures," it said. It added that the matter was earlier transferred to the "religious committee" upon the NHRC's directive.

"Thereafter, a letter was received from the Home Police-II Department dated 03/03/2021 where they cited

the HC order of 2015 in WPC no 5234/2011 wherein it was directed to demolish the entire construction above the ground floor as well as portions of the ground where idols are not installed/placed without waiting for the decision of the Religious Committee," the statement said.

According to a notice dated July 7, the office of the Block Development Officer (South) directed the "encroachers/unauthorised occupants" to remove the encroachment within three days.

"Now, therefore, all the encroachers/unauthorised occupants on the above said gaon sabha land are hereby directed to remove the encroachment themselves within three days from the date of issue of this notice falling which the action for removal of illegal encroachment upon the Gram Sabha land shall be initiated by this office and the cost of demolition shall be recovered from the encroachers," the notice read.